

अनुदान संख्या 32 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 32 - DIRECT TAXES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	7036,44,00		
			7218,40,00	-263,01,93
पूरक	Supplementary	181,96,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			177,72,73
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	302,00,00		
			302,04,00	-74,69,96
पूरक	Supplementary	4,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			67,07,35

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹26301.93 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए ₹18196.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹26301.93 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹18196.00 lakhs obtained in March, 2020 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	686053.00			
पू.	S.	18196.00	686476.27	678157.28	-8318.99
पु.	R.	-17772.73			

(I) "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत — बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) "अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" — ₹8877.91 लाख की बचत (₹15523.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन तथा प्रचार, चिकित्सा दावों, कम दौरे किए जाने, नए स्थल किराए पर लिए जाने, आईटी अधिप्राप्तियों, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कार्य/सेवाएं पूरा न होने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(खा) "संगठन और प्रबंधन सेवाएं" — ₹26217.65 लाख की बचत (₹82570.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यों/सेवाओं के पूरा न होने, लॉकडाउन के कारण बीजक प्राप्त न होने, प्रकाशन तथा प्रचार कार्यकलाप कम होने, आईटी अधिप्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों और कम दौरे किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) "आसूचना" — ₹1308.75 की बचत (₹10777.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, नए स्थल किराए पर लिए जाने, आईटी अधिप्राप्तियों, अन्य स्थापना संबंधी खर्चों तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(I) Under "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research, Statistics and Publication" - saving of ₹8877.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15523.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity, medical claims, tours undertaken, hiring of new spaces, IT procurements, non-completion of works/services owing to COVID-19 lockdown and economy measures.

(B) "Organisation and Management Services" - saving of ₹26217.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹82570.10 lakhs) was due to non-completion of works/services, non-receipt of invoices owing to lockdown, less publications and publicity activities, requirement of less funds towards IT procurements, medical reimbursement claims and less tours undertaken.

(C) "Intelligence" - saving of ₹1308.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10777.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salary, medical reimbursement claims, hiring of new spaces, IT procurements, other establishment related expenses and economy measures.

(II) “संग्रहण प्रभार – आयकर” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई :-

(का) “आयकर तथा धन कर मामलों संबंधी समझौता आयोग” – ₹773.41 लाख की बचत (₹2878.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय” – ₹1065.52 लाख की बचत (₹9499.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, स्थापना संबंधी खर्चों, कम दौरे किए जाने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹262.18 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें “संग्रहण प्रभार – आयकर – आयुक्त तथा उनके कार्यालय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹12262.90 लाख का अधिक व्यय (₹18196.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹594191.90 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, अन्य स्थापना संबंधी खर्चों तथा व्यावसायिकों को लेने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की वजह से हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(II) Under “Collection Charges-Income Tax” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases” - saving of ₹773.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2878.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards establishment related expenses and economy measures.

(B) “Zonal Account Offices of Principal Chief Controller of Accounts” - saving of ₹1065.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9499.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, establishment related expenses, less tours undertaken and economy measures.

(III) Under one head saving of ₹262.18 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under “Collection Charges - Income Tax - Commissioners and their offices” - excess of ₹12262.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹594191.90 lakhs including supplementary grant of ₹18196.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, other establishment related expenses and hiring of professionals.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"			
लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	19945.00		
पू.	S.	2.00	14289.56	13681.80
पु.	R.	-5657.44		-607.76
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"			
आवास पर पूँजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	10055.00		
पू.	S.	2.00	9116.12	8975.52
पु.	R.	-940.88		-140.60
(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।		(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.		
(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवन निर्माण" के अंतर्गत – ₹6262.20 लाख की बचत (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19944.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद/निर्माण के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने/उनके फलीभूत न होने तथा परियोजनाओं की संशोधित अनुमानित लागत के कारण परियोजनाएं शुरू करने में विलंब होने के कारण हुई।		(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Acquisition of Land & Construction of Building for Income Tax Department" - saving of ₹6262.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19944.00 lakhs including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) was due to non-materialisation/non-fructification of proposals towards purchase/construction of properties and delay in commencement of projects owing to revised estimates of cost of projects.		

(III) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवसीय भवन – आयकर कर्मचारियों के लिए आवसीय भवन – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और आवसीय भवन का निर्माण” के अंतर्गत – ₹1081.48 लाख की बचत (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10057.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद/निर्माण के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Land & Construction of Residential Building For Income Tax Department” - saving of ₹1081.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10057.00 lakhs including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) was due to non-materialisation of proposals for purchase/ construction of properties.
